"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2003—कार्तिक 2, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ. ए. 4-22/2002/1/एक.—श्री पी. सी. नायक, माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर को निम्नांकित अवधि का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

1. दिनांक 28-7-2003 से 5-8-2003 (9 दिवस)
2. दिनांक 11-8-2003 से 21-8-2003 (11 दिवस)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

क्रमांक ई-7-3/2003/1/2/लीव.—डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 13-10-2003 से 17-10-2003 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा साथ ही दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 अक्टूबर, 2003 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. आलोक शुक्ला को आगामी आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. आलोक शुक्ला को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. डॉ. आलोक शुक्ला के अवकाश की अवधि में उनका कार्य श्री बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

फा. क्रमांक 6467/डी-4365/21-ब/03.—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से नीचे सारणी के कॉलम (1) में दर्शाए प्रत्येक जिलों के लिए उक्त सारणी के कॉलम (2) में उससे संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए दिनांक 2-10-2003 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी

जिला का नाम (1)	विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय का नाम (2)
दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा	सत्र न्यायालय, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा
जशपुर	सत्र न्यायालय, जशपुर

यह अधिसूचना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन, विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 1-2-90-इक्कीस-बी(1), दिनांक 30 जनवरी, 1990 जहां तक कि वह सत्र खण्ड रायगढ़ के गठन से संबंधित है.

तथा म. प्र. शासन, विधि विभाग की अधिसूचना क्र. 1-2-90-इक्कीस-बी (1), दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 जहां तक कि वह सत्र खण्ड बस्तर के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय के संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा तथा जशपुर के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय बस्तर एवं रायगढ़ में दिनांक 2-10-2003 को लंबित है, क्रमश: विशेष न्यायालय दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा तथा जशपुर को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 9th October, 2003

F. No. 6467/D-4365/XXI-B/03.—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby specifies for each of the Districts mentioned in Column No. (1) of the Table below, a Court of Session specified in the corresponding entry in Column No. (2) of the said Table to be the Special Court to try the offences under the said Act with effect from 2-10-2003 :—

TABLE

Name of the District (1)	Name of the Court of Session to be Special Court (2)
.Dakshin Bastar, Dantewada, Jashpur	Court of Sessions Judge, Dakshin Bastar, Dantewada, Court of Sessions Judge, Jashpur.

This notification modifies the M. P. Government, Law Department Notification F. No. 1-2-90-XXI-B (1), dated 30th January, 1990 so far as it relates to erstwhile Sessions Division, Raigarh.

And M. P. Government Law Department's Notification No. 1-2-90-XXI-B (1) dated 26th October, 1995 so far as it relates to erstwhile Sessions Division, Bastar for specifying a Court of Session under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989).

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Courts Dakshin Bastar, Dantewada and Jashpur and pending in the Special Courts at Bastar and Raigarh respectively as on 2-10-2003 shall stand transferred to the Special Courts constituted at Dakshin Bastar Dantewada and Jashpur respectively.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

क्रमांक 6469/डी-4366/21-ब.—स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के परामर्श से, नीचे दी गई सारणी के कालम नम्बर-2 में उससे संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए दिनांक 2-10-2003 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	विशेष न्यायालय दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा.	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
2.	विशेष न्यायालय, जशपुर	जशपुर

यह अधिसूचना स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (क्रमांक 61 सन् 1985) की धारा 36 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-6-89-21-ब (एक) दिनांक 2-4-1998 को जहां तक कि सत्र खण्ड बस्तर एवं रायगढ़ के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा तथा जशपुर के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय बस्तर एवं रायगढ़ दिनांक 2-10-2003 को लंबित है को क्रमशः विशेष न्यायालय दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा एवं जशपुर को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 9th October, 2003

No. 6469/D-4366/XXI-B.—In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), The State Government, with the concurrence of the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, hereby constitute Special Court as specified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule from the date the Judge of the Special Court assumes the charge of his office in the said court, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Special Court (2)	Local area/Sessions Division. (3)
1.	Special Court, Dakshin Bastar, Dantewara.	Dakshin Bastar, Dantewara.
2.	Special Court, Jashpur	Jashpur

This notification modifies the Madhya Pradesh Government Law Department's Notification No. 1-6-89/XXI-B (I) dated 2-4-98 so far as it relates to erstwhile Sessions Division Bastar and Raigarh for specifying a court of Session under Section 36 of the Said Act.

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Court Dakshin Bastar and Jashpur and pending in the Special Court Bastar and Raigarh respectively as on 2-10-2003 shall stand transferred to Special Courts constituted at Dakshin Bastar, Dantewara and Jashpur respectively.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

फा. क्रमांक 6473/डी-4302/21-ब/03.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायाधीशों को उसके कॉलम नं. (3) में इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए दिनांक 2-10-2003 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा.	दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
2.	सत्र न्यायाधीश, जशपुर	जशपुर

यह अधिसूचना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1-1-88-21-ब, दिनांक 10-3-1992 को जहां तक कि सत्र खण्ड बस्तर एवं रायगढ़ के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा तथा जशपुर के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय बस्तर एवं रायगढ़ में दिनांक 2-10-2003 को लंबित है को क्रमश: विशेष न्यायालय दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा एवं जशपुर को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 9th October, 2003

F. No. 6473/D-4302/XXI-B/03.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby appoints the Sessions Judge the specified in column (2) of the Schedule below to be the Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column (3) thereof to trial the cases exclusively relating to offence mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section of the said Act with effect from 2-10-2003.

SCHEDULE

S. No. (1)	Special Court (2)	Local area/Session Division. (3)
1.	Sessions Judge, Dakshin Bastar, Dantewara.	Dakshin Bastar, Dantewara.
2.	Sessions Judge, Jashpur	Jashpur

This notification modifies the Madhya Pradesh Government Law Department's Notification No. 1-1-88-21-B, dated 10-3-92 so far as it relates to erstwhile Sessions Division Bastar and Raigarh for specifying a court of Sessions under Section 3 of the said Act.

All cases arising out of the area comprised within the jurisdiction of Special Court Dakshin Bastar Dantewara and Jashpur and pending in the Special Court of Bastar and Raigarh respectively as on 2-10-2003 shall stand transferred to Special Court constituted at Dakshin Bastar, Dantewara and Jashpur respectively.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2003/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की संख्या 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 1-10-2003 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के समक्ष कालम 3 में दर्शाये गये जिले में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर पदस्थ करता है :—

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	प्रस्तावित पदस्थापना (3)
1.	श्री छबिलाल पटेल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा, अंबिकापुर.
2.	श्री तपन कुमार चक्रवर्ती अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रायपुर.
3.	श्री खेलन दास चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग.

Raipur, the 13th October, 2003

No. F 5-17/Food/2003/29.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1-A) of Section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government in continuation of the order of Hon'ble High Court of Chhattisgarh dated 1-10-2003 hereby post the following officers of Chhattisgarh Higher Judicial Service on deputation, as President, District Consumer Forum of the district mentioned aginst their names in column No. 3 temporarily until further orders with effect from assuming their duties :—

No. (1)	Name of the Officers (2)	District (3)
1.	Shri Chhabilal Patel Addl. District & Session Judge, Dhamtari.	President, District Consumer Forum, Surguja, Ambikapur.
2.	Shri Tapan Kumar Chakrawarti, Addl. District & Session Judge, Mungeli.	President, District Consumer Forum, Raipur.
3.	Shri Kelan Das IV Addl. District & Session Judge, Durg.	President, District Consumer Forum, Durg.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, संयुक्त सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ 73/181/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "ऑपटेक यूनिवर्सिटी" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "ऑपटेक यूनिवर्सिटी" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 17th September 2003

No. F-73/181/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "APTECH UNIVERSITY" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "APTECH UNIVERSITY" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-132/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तक्नीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है, जो "टेकआर्ट इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "टेकआर्ट इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 22nd September 2003

No. F-73-132/2003/ H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "TECHART INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "TECHART INTERNATIONAL UNIVERSITY, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2003

क्रमांक 124/सउशि/2003.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत "दी ग्लोबल यूनिवर्सिटी" रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत, विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उपनियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है, तथा उपनियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 30 प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

THE GLOBAL UNIVERSITY

Established under Section 5 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhniyam 2002, vide Notification of the Government of Chhattisgarh F-73-116/2003/HE/38 dated 6th August 2003

FIRST STATUTES

Made in accordance with the provisions in Section 25 of the Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002

1.0 Short Title, Extent and Commencement

1.1 These Statutes shall, here-in-after be called, The First Statutes of the Global University 2003.

1.2 These First Statutes are applicable to The Global University and any matter relating and incidental thereto.

1.3 These First Statutes shall come into force on the date of publication of these First Statutes by the Government of Chhattisgarh in the Official Gazette.

1.4 The Registered office of The Global University shall be located at Raipur.

2.0 Definitions (in alphabetic order)

In these First Statutes unless and otherwise the context demands :

2.1 **Academic Centres** means Distance Education Academic Centres approved by the University for imparting education in formal/nonformal mode in respect of any or all courses offered by the University and even in new innovative courses not offered by the University but approved by them and located within or outside the State of Chhattisgarh in India and abroad. Such centres shall be designated as Distance Education Academic Centres (DEAC). Such Centres shall function independently within the framework of the University norms.

2.2 **Academic Council** means the Academic Council constituted under Section 22 of the Act and under Section 13.0 of these First Statutes.

2.3 **Academic Staff** means such categories of staff as are designated as academic staff by the ordinances.

2.4 **Academic Year** ordinarily means the period from 01 July of any year to 30th June and from 01 January to 31 December of the following year or the dates announced by the Academic Council for a particular academic session.

2.5 **Act** means, the Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002.

2.6 **Ad-hoc Committee** means a committee constituted under the Section 19.0 of these First Statutes.

2.7 **Administrator** means the officer appointed by the Governing Body to exchange correspondence on behalf of the University, to sign and

authenticate records on behalf of the University, to obtain reports and returns from Colleges and Schools of the University and to liaise with the State Government, UGC and other State Authorities, to generally supervise the administrative functions of the University and to manage the office of the Registrar in his absence.

2.8 **Affiliation** means and includes together with its grammatical variations in relation to all institutions, colleges and schools, recognition of such institutions, colleges, schools by association of such colleges and schools with, and admission of such schools, colleges, institutions to the privileges of a University. These institutions, schools and colleges may be located in or outside the State of Chhattisgarh which includes outstation and foreign countries.

2.9 **Authorities** means authorities mentioned under Section 19 of the Act, and Section 9.0 of these First Statutes.

2.10 **Board** means the Board of Management of the University constituted under Section 21 of the Act and Section 11.0 of these First Statutes.

2.11 **Board of Studies** means the Board of Studies of the University for each subject or group of subjects constituted by the Academic Council.

2.12 **Chancellor** means the Chancellor of the University as mentioned in Section 14 of the Act and Section 4.0 of these First Statutes.

2.13 **Committee** means all committees constituted under Sections 15, 16, 17, 18, 19 and 20 of these First Statutes.

2.14 **Common Seal** means the authoritative seal of the University established under Section 6 of the Act.

2.15 **Courses** include programmes and courses of studies imparted in the formal mode and/or in the non-formal/distance education mode in the institutions, colleges, schools and/or Study Centres of the University.

2.16 **Dean (College)** means the person responsible for the upkeep, development and proper utilization of infrastructural facilities of the respective school/ college and fulfil the academic requirements of the system.

2.17 **Dean (Planning and Monitoring)** means the person responsible for the preparation, monitoring and implementation of the plans of the University.

2.18 **Dean (Research)** means the person responsible for the execution and monitoring of the research schemes formulated and approved by the University Research Board.

2.19 **Dean (Students Welfare)** means the person responsible for looking after the campus amenities and general welfare of the students of schools and colleges of the University.

2.20 **Dean (Discipline)** means the person responsible for maintaining the discipline amongst the students of schools and colleges of the University.

2.21 **Director** means the officer appointed by the Governing Body for coordinating the functions and activities of the Dean of schools, colleges and study centres and to manage the affairs of the University in the absence of the Vice Chancellor.

2.22 **Distance Education** means the education/courses/programmes offered to the students on off campus mode. It includes system of imparting education through any means of communication such as providing printed lessons, broadcasting, contact programmes, internet, e-learning or the combination of any two or more of such means.

2.23 **Employee** means and includes and person appointed by the University.

2.24 **Finance Committee** means the Finance Committee constituted under Section 23 of the Act of Section 17.0 of these First Statutes.

2.25 **Financial Year** means the period commencing on the 1st April of any year and ending with 31st March of the following year or any period as prescribed by the Governing Body.

2.26 **Fund means the General Fund** established under Section 7 of the Act and Section 22.0 of these First Statutes.

2.27 **Government means** the Government of the State of Chhattisgarh.

2.28 **He** includes she and His includes Her.

2.29 **Institute** means and includes institute, institution, schools and colleges constituted as part of the University to impart education in specified disciplines located within or outside the State of Chhattisgarh in India and/or Abroad

2.30 **Main Campus** means the campus of the University, Colleges and Schools located at Raipur in particular and the adjoining districts in general.

2.31 **Manual of Instructions** includes all rules, procedures, instructions and systems laid down by various Committees, Boards, Authorities, Officers of the University for the purposes of smooth functioning of the University.

2.32 **Ordinance** means ordinances issued by the University as prescribed by Section 25 of the Act.

2.33 **Planning Committee** means the planning committee of the University.

2.34 **Regulations** means Regulations made under Section 37 of the Act.

2.35 **Rules** means the Rules made under Section 36 of the Act.

2.36 **Sponsoring Body** means the Institute of Ecology and Environment Society, registered under the provisions of Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973.

2.37 **Staff** means the teaching and non-teaching employees of the University who are on the payroll of the University and does not include any casual, temporary, contractual, adhoc employees or visiting persons who may be engaged for a specific assignment or task.

2.38 **States** means the States of India.

2.39 **Statutes** means the Statutes made under Section 25 and 26 of the Act and includes the amendments, alterations and modifications to the Statutes.

2.40 **Student** means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any course of study at the University or Institutes, Study Centres, Academic Centres and Colleges affiliated and/or associated to the University.

2.41 **Study Centres** means Distance Education Centres approved by the University under the advice of the Governing Body for imparting education in non-formal and distance mode in respect of any or all courses offered by the University and located within or outside the State of Chhattisgarh in India and abroad. Such Study Centres for convenience may be designated as Delhi Campus, Mumbai Campus, Bangalore Campus, Hyderabad Campus, Patna Campus, Pune Campus, Gurgaon Campus, Noida Campus, Kolkata Campus, London Campus, Oxford Campus, Cambridge Campus and likewise.

2.42 **University means** The Global University established under Section 5 of the Act and will have the same meaning as stated in Section 2 (f) of the University Grants Commission Act 1956 as amended from time to time.

2.43 **Vice Chancellor** means the Vice Chancellor of the University appointed within the meaning of Section 15 of the Act and Section 5.0 of these First Statutes.

2.44 **Visitor** means the Visitor as defined under Section 13 of the Act.

3.0 **Objects of the University** The objects of the University are listed in succeeding paragraphs :

3.1 To provide for instructions in all branches of learning in Higher Education as the University may consider appropriate and to make provision for research, advancement and dissemination of knowledge.

3.2 To establish main campus in the State of Chhattisgarh and to affiliate Institutions, approve Study Centres, Academic Centres and Off-Campus Institutions at different locations in India and abroad.

3.3 To create higher levels of intellectual abilities.

3.4 To institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of assignments and examinations, or any other mode of evaluation and assessment as laid down by the Academic Council.

3.5 To withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions for good and sufficient cause as recommended by the Academic Council.

3.6 To offer continuing and distance education programmes.

3.7 To ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the related regulatory bodies and authorities.

3.8 To encourage and promote research activities and set up centres of excellence for pure and applied research and development, and institute awards and fellowships for undertaking research at University as well as at other Institutions/Centres of the University in India and abroad.

3.9 To affiliate, recognize or collaborate with any other college, university, research institution, industry association, professional association or any other organisation in India or abroad to conceptualize, design and develop specific educational and research programmes, training programmes, exchange programmes and any such other programmes which the University may consider appropriate for students, faculty members and others.

3.10 To undertake surveys, studies and consultancy for any organisation in India or abroad.

3.11 To undertake programmes for the training and development of faculty members of the University and other institutions in India or abroad.

3.12 To undertake collaborative research with any organisation in India or abroad and undertake commercialisation of technologies.

3.13 To develop, register and license all forms of Intellectual property rights including trademarks, copyrights, know-how and patents, etc.

3.14 To conceptualise, design, develop and commercialise various products, equipments and machinery as part of the research and development activity

3.15 To establish State-of-the-art facilities for the promotion and advancement of education, training and research activities.

3.16 To establish Examination Centres within and outside Chhattisgarh in India as well as in other countries.

3.17 To confer Honorary degrees and other academic distinctions in the manner laid down in the Statues.

3.18 To encourage sports, cultural, extra curricular and co-curricular activities for the students and the staff.

3.19 To do all things necessary to promote the above objectives.

3.20 To pursue any other objective as may be approved by the Governing Body but within the framework of the University Act (2 of 2002)

3.21 To pursue any other objective as may be approved by the State Government.

4.0 Appointment and Powers of the Chancellor

4.1 The Chancellor shall be appointed by the Sponsoring Body with the prior approval of the Visitor.

4.2 The term of office of the Chancellor shall be three years.

4.3 The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and the Head of the University.

4.4 The Chancellor shall preside over the Convocation of the University, when the Visitor is not present.

4.5 The Chancellor shall have the following powers :

4.5.1 To call for any information or record.

4.5.2 To appoint the Vice Chancellor.

4.5.3 To remove the Vice Chancellor.

4.5.4 To exercise such other powers as may be delegated to him by the Governing Body.

4.6 If in the opinion of the Sponsoring Body, the actions of the Chancellor are in any way detrimental to the interests of the University, it may with prior approval of the Visitor, recall and replace the Chancellor. The Sponsoring Body shall appoint such other person as may be found appropriate in the position of Chancellor to succeed the person so acting with the prior approval of the Visitor.

5.0 Appointment, Powers and Duties of the Vice Chancellor

5.1 The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body.

5.2. The term of the office of the Vice Chancellor shall initially be for a period of four years. He may be reappointed for another term not exceeding four years by the Chancellor.

5.3 The Vice Chancellor shall be principal academic officer of the University and also be the ex-officio member of the Governing Body, Board of Management, Academic Council, and such other Committees that may be set up by the Governing Body or the Board of Management from time to time.

5.4 The Vice Chancellor shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the various authorities of the University, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Act and the Statues.

5.5 If in the opinion of the Vice Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter of which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter.

Provided that if in the opinion of the concerned authority such action should not have been taken by the Vice Chancellor then such case shall be referred to the Chancellor whose decision there on shall be final.

Provided further that where any such action taken by the Vice Chancellor affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Body and the Governing Body may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice Chancellor.

5.6 If the opinion of the Vice Chancellor any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by the Act, Statutes or Ordinances is likely to be prejudicial to the interests to the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within seven days from the date of its decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within seven days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

5.7 If at any time upon representation being made or otherwise, and after making such enquiries as may be deemed necessary, the Chancellor on the recommendations of the Governing Body may by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

5.8 The Vice Chancellor may consititute such committees as he deems necessary to help him in the discharge of the duties entrusted to him or under the Act.

5.9 The Vice Chancellor may sanction an allowance to an employee of the University for any special duties assigned to such an employee or additional duties performed by him which in the opinion of the Vice Chancellor warrants such payments.

Provided that such allowance shall not exceed twenty percent of the basic salary of such employee.

5.10 The Vice Chancellor may sanction such posts as he deems necessary to help him in the discharge of his duties.

6.0 Appointment, Powers and Duties of the Registrar

6.1 The Registrar shall be appointed by the Vice Chancellor, based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose, with the approval of the Chancellor.

6.2 The Selection Committee shall consist of the following members :

i) One Representative of the Vice Chancellor.
ii) One Representative of the Sponsoring Body, who is also a member of the Governing Body.
iii) One expert nominated by the Sponsoring Body, who is not in any way connected with the University.

6.3 The term of office of the Registrar shall not exceed 3 years.

6.4 The Registrar shall have such qualifications and experience and draw such emoluments as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

6.5 The Registrar shall undertake all such functions and reponsibilities as may be specified by the Governing Body, the Board of Management and the Vice Chancellor.

6.6 The Registrar shall be the ex-officio non-member Secretary of the Board of Management and ex-officio Secretary of the Academic Council and such other authorities and bodies as may be constituted by or under the Act, the Statutes and the Ordinances as recommended by the Board of Management.

6.7 The Registrar shall report of the Vice Chancellor.

6.8 The following shall be the duties of the Registrar :

(i) To be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Governing Body or the Board of Management shall commit to his charge.

(ii) To exchange the official correspondence on behalf of the authorities of the University.

(iii) To make Agenda and issue Notices of meetings of the authorities of the University and all Committees and Sub-Committees appointed by any of these authorities with the approval of the Vice Chancellor.

(iv) To keep the minutes of the meetings of the all the authorities and Sub-Committee appointed by any of these authorities and circulate the same among the members, with the approval of the Vice Chancellor.

(v) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and pleadings or depute as representatives for this purpose.

(vi) To sign contracts and documents and authenticate records on behalf of the University.

(vii) To submit information, reports and documents to the Government and liaise with the State Government, Central Government, University Grants Commission and other Government authorities.

(viii) To generally supervise the administrative functions of the University.

7.0 Appointment, Powers and Duties of the Controller of Examination :

7.1 The Controller of Examination shall be appointed by the Vice Chancellor on the recommendations of the Selection Committee appointed for the purpose.

7.2 The Selection Committee shall consist of :

7.2.1 The Vice Chancellor - Chairman

7.2.2 The Registrar

7.2.3 One Representative of the Sponsoring Body, who is also a Member of Governing Body.

7.2.4 One Representative of the Sponsoring Body, who is not in any way connected with the University.

7.3 The Controller of Examination shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

7.4 The Controller of Examination shall draw such salary, allowances and perquisites which shall be fixed by the Board of Management from time to time.

7.5 The term of office and the conditions of appointment of the Controller of Examination shall be laid down in the order of appointment issued by the Vice Chancellor.

7.6 The Controller of Examination shall report to the Vice Chancellor.

7.7 The following shall be the duties of the Controller of Examination :

7.7.1 He shall be fully responsible for the timely and smooth conduct of the combined entrance test and the end-semester/year examinations.

7.7.2 He shall lay down the guidelines for the setting up of the examination papers.

7.7.3 He shall appoint internal as well as external examiners through the Examination Committee for each subject and get at least 2 sets of question papers prepared well in advance.

7.7.4 He shall appoint a Moderation Committee and get all papers moderated before these are sent for printing.

7.7.5 He shall ensure strict security of the examination papers.

7.7.6 He shall ensure timely dispatch of answer books and admit cards to all examination centres.

7.7.7 He shall be responsible for getting the answer books evaluated in accordance with the guidelines laid down by the paper setter.

7.7.8 He shall be responsible for getting the results compiled accurately and declared on time.

7.7.9 He shall be responsible for re-evaluation of the answer books on request from the students for a fee as prescribed by the Board of Management.

8.0 Appointment, Powers and Duties of the Chief Finance and Accounts Officer.

8.1 The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Vice Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose.

8.2 The Selection Committee shall consist of :

8.2.1 The Vice Chancellor - Chairman.

8.2.2 One Representative of the Chancellor.

8.2.3 One Representative of the Sponsoring Body who is also a Member of the Governing Body.

8.2.4 One Expert Nominated by the Sponsoring Body who is not in any way connected with the University.

8.3 The Chief Finance and Accounts Officer shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

8.4 The Chief Finance and Accounts Officer shall draw such salary, allowances and be entitled to such perquisites which shall be fixed by the Board of Management from time to time.

8.5 The term of office and the terms of appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be as mentioned in his order of appointment by the Vice Chancellor.

8.6 The Vice Chancellor may appoint a person to officiate as the Chief Finance and Accounts Officer, in the event of temporary absence of the Chief Finance and Accounts Officer.

8.7 The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise general supervision over the funds of the University and shall have such powers and responsibilities as may be delegated or assigned to him by the Board of Management or the Finance Committee.

8.8 The Chief Finance and Accounts Officer shall report to the Vice Chancellor.

9.0 Authorities of the University :

9.1 The Governing Body.

9.2 The Board of Management

9.3 The Academic Council

9.4 The Finance Committee

9.5 The Examination Committee

The powers and functions of the authorities will be as per the following paragraphs.

10.0 The Governing Body :

The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

10.1 Constitution of the Governing Body:

The Governing Body shall consist of the following members :

10.1.1 The Chancellor

10.1.2 The Vice Chancellor

10.1.3 Three Persons nominated by the Sponsoring Body.

10.1.4 One Representative of the State Government.

10.1.5 One Educationist of repute to be nominated by the State Governme[illegible]

10.1.6 One Academician to be nominated by the Visitor.

The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body

10.2 Term of the Governing Body

The Members of the Governing Body shall have a term of 4 years.

10.3 Disqualifications of the Members of the Governing Body

The Members of the Governing Body shall cease to be the Member under the following circumstances :

10.3.1 If the member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

10.3.2 If the act and conduct of a member is detrimental to the interest of the University, the Sponsoring Body shall have the powers to replace or recall any such member in consultation with the nominating authority.

10.4 Powers and Functions of the Governing Body

10.4.1 The Governing Body shall have the following powers :

(i) To appoint the Director, to coordinate the functions and activities of the Deans of Schools, Colleges and Study Centres and to manage the affairs of the University in the absence of the Vice Chancellor.

(ii) To appoint all Deans and Administrator(s).

(iii) To appoint Auditors of the University.

(iv) To oversee the performance and review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the Act, Rules, Statutes or Ordinances.

(v) To approve the Annual Report and Accounts of the University.

(vi) To lay down the policies of the University.

(vii) To take decision about the voluntary liquidation of the University.

(viii) To delegate such powers as it may deem fit to the Board of Management and other authorities or officers of the University.

10.4.2 The Governing Body shall perform such other functions and have such other powers as are not otherwise provided for and are necessary for proper functioning and administration of the University.

10.5 Reserved Powers of the Governing Body

10.5.1 In case of any deadlock in the functioning of the Board of Management and if in the opinion of the Governing Body the business of the University cannot be transacted in the normal course, the Governing Body shall have the powers to do all necessary things including superseding the Board of Management and forming a new Board to facilitate smooth functioning of the University.

10.5.2 The Governing Body may also exercise the reserved powers suo-moto or as and when a written report is submitted by any officer or authority of the University to the Chancellor or the Vice Chancellor about the deadlock in the functioning of the Board.

10.5.3 Upon receipt of such a report the Chancellor or the Vice Chancellor shall convene a special meeting of the Board within 5 working days for restoration of normally of operations.

10.5.4 The decisions taken by the Govening Body and implemented by the Officers under the clause shall be final and binding on all Members of the Board and on all the Members of the Governing Body.

10.6 Meetings of the Governing Body

10.6.1 The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year, on any working day, at the headquarters of the University or at any other location(s) as agreed to by majority of the Members.

10.6.2 The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and shall preside over the meetings of the Governing Body. In the absence of the Chancellor, the Vice Chancellor shall preside over the meeting.

10.6.3 A notice of 07 days shall be given to the Members stating the agenda for the meeting. A notice of less than 07 days may be considered sufficient if majority of the members agree of such a shorter notice.

10.6.4 The quorum of the meeting shall be 5 Members present in person.

10.6.5 Each Member of the Governing Body including the presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be adopted by simple majority.

10.6.6 The presiding officer of the meeting shall cause the minutes of the meeting to be recorded and circulated to the members within a period of one month from the date of such a meeting.

10.7 Extraordinary Meeting of the Governing Body

10.7.1 In the event of exigency, the Chancellor and the Vice Chancellor may call for an extraordinary general meeting of the Governing Body.

10.7.2 The Sponsoring Body, may in the event of exigency and/or in the interest of the administration of University, in consultation with the Chancellor or the Vice Chancellor call for an extraordinary meeting of the Governing Body by circulating a resolution amongst the Members.

10.7.3 The Chancellor or the Vice Chancellor may, under exigencies, obtain the consent of the Governing Body by circulating appropriate resolution among its members any such resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Governing Body.

11.0 The Board of Management

The Board of Management shall be the principal executive body of the University.

11.1 Consittution of the Board of Management

11.1.1 Following Members shall constitute the Board.

(i) The Vice Chancellor (Ex-Officio).

(ii) Two Nominees of the Sponsoring Body.

(iii) One Representative to be nominated by the State Government.

(iv) Senior most Professor of the University to be nominated by the Vice Chancellor.

11.1.2 The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Board and the Registrar shall be the non-member Secretary.

11.1.3 The Vice Chancellor shall preside over the meetings of the Board and in the absence of the Vice Chancellor one of the Nominees of the Sponsoring Body shall conduct the proceedings of the meeting.

11.1.4 The tenure of the Members of the Board of Management shall be three years, except in the case of Ex-Officio Members.

11.2 Disqualifications of the Members of the Board.

The members of the Board of Management shall cease to be the member under the following circumstances :

11.2.1 If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

11.2.2 If in the opinion of the Chancellor, a Member of the Board acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may in consultation with the nominating authority ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

11.3 Meetings of the Board :

11.3.1 The Board of Management shall meet as often as necessary, and at least once in three calendar months.

11.3.2 The meetings shall be convened by the Registrar.

11.3.3 A notice of 07 days shall be given for the meeting provided that an emergency meeting may be convened at the discretion of the Vice Chancellor at a short notice of not less than 02 days.

11.3.4 The quorum of the meeting shall be 3 members present in person.

11.3.5 Each member of the Board including the Chairman/Presiding Officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be taken by simple majority. In case of a tie, the presiding officer shall exercise a casting vote.

11.3.6 The Registrar shall cause recording of minutes of the meeting, with the approval of the Vice-Chancellor and circulate them to the member concerned within a period of one month from the date of conduction of the meeting.

11.3.7 The Vice Chancellor may, under exigencies, obtain the consent of the Board by circulating appropriate resolution among its Members and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.

11.4 Powers and Functions of the Board of Management

The Board of Management shall have the powers to take all the necessary decisions for smooth and efficient functioning of the University. The Powers shall interalia include but not be limited to the following:

11.4.1 Staffing :

11.4.1.1 To manage and administer all revenues and properties of the University and to conduct all administrative affairs of the University not otherwise specifically provided for.

11.4.1.2 To create teaching, academic, administrative, ministerial and other necessary posts and to decide on the number, qualifications and cadre thereof, and to determine the emoluments for such posts in consultation with the Finance Committee.

11.4.1.3 To appoint Directors, Associate Directors, Principals, Vice Principals, Deans, Associate Deans, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Senior Lecturers, Junior Lecturers, Operational Staff, Administrative, Ministerial and other Staff as may be necessary on recommendations of the Selection Committee.

11.4.1.4 To lay down rules in respect of emoluments and duties of the various academic and non-academic staff recruited by the University.

11.4.1.5 To lay down rules for appointment of Visiting Fellows, Visiting Professors, Professor Emeritus, Consultants, Scholars and determine their terms and conditions of such appointments.

11.4.1.6 To appoint internal auditors to undertake audit of the various functions of the University.

11.4.2 Academic Matters

11.4.2.1 To generally lay down, in consultation with the Academic Council, the academic policies, education and teaching standard and policies relating to students' admission, examinations and award of degrees, diplomas and certificates and other academic awards or distinctions.

11.4.2.2 To establish, on the advice of the Academic Council, Schools and Colleges specific to a discipline of Higher Education and to allocate areas of Study, Teaching and Research to them.

11.4.2.3 To institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the Regulations.

11.4.2.4. To lay down rules regarding the emoluments and travelling and other allowances of examiners appointed for examination, tabulation and such other personnel appointed for examination, in consultation with the Academic Council and the Finance Committee.

11.4.2.5 To acquire intellectual property rights, copyright, trade marks and the like from any institution or organisation, on such terms and conditions as the Board may determine, and pay such compensation for the acquisition as may be just and equitable.

11.4.3 Finance :

11.4.3.1 To consider the budget as recommended by the Finance Committee and to approve the same with or without modifications.

11.4.3.2 To manage and administer the revenues, regulate the finance, accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University and for that purpose appoint such agent(s)/ representative(s)/consultant(s) it may deem fit.

11.4.3.3 To opern account(s) of the University with any one or more nationalised/scheduled banks and to lay down the procedure for operating the same.

11.4.3.4 To draw, accept, make, endorse, discount and negotiate securities of the Government promissory notes, Bills of exchange, Cheques or other negotiable instruments.

11.4.3.5 To receive and give grants, donations, contributions, gifts, prizes, scholarship, fees and other moneys.

11.4.3.6 To purchase, take on lease, accept as gift or otherwise any land or buildings or work which may be required for the purposes of the University on such terms and conditions as deemed appropriate and to construct or alter and maintain any such buildings or works.

11.4.3.7 To transfer or accept transfers of any moveable property on behalf of the University.

11.4.3.8 To advise the Sponsoring Body on matters regarding acquisition, management and disposal of any immovable property on behalf of the University.

11.4.3.9 To execute in consultation with the Sponsoring Body, conveyance, transfer, re-conveyances, mortgages, leases, bonds, licenses and agreements in respect of property, moveable or immovable, belonging to the University or to be acquired for the purposes of the University.

11.4.3.10 To provide building(s), premises, furnitures, fittings, equipments, appliances and other facilities required for smooth functioning of the University.

11.4.3.11 To appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit.

11.4.3.12 To invest the funds of the University or money entrusted to the University, in such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment.

11.4.3.13 To raise and borrow notes or other obligations or securities in consultation with the Sponsoring Body by providing properties and assets of the University as security, or borrow money without any securities, and upon such terms and conditions as it may think fit, and to pay out of the funds of the University, all expenses, incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed.

11.4.3.14 To establish, maintain and operate the General Fund as stipulated in Section 7 and 8 of the Act and Section 22.0 of these First Statutes.

11.4.3.15 To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts including the Balance Sheet for every previous financial year, in such form as may be prescribed by the Regulations and submit the same to the Governing Body for their approval.

11.4.3.16 To fix limits of the total non-recurring expenditure for a year on the recommendations of the Finance Committee.

11.3.4 Students' Affairs :

11.4.4.1 To regulate and enforce discipline among the students of the University and to take appropriate disciplinary action wherever necessary.

11.4.4.2 To entertain and adjudicate upon appeals and grievance of the students of the University through the Committees set up for the purpose.

11.4.4.3 To establish and regulate the maintenance of hostels for the students for the University and recognise hostels established by outside parties on the basis of the recommendations of a committee established for the purpose.

11.4.5 Administrative and Legal Matters :

11.4.5.1 To enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and to do all such acts as are necessary to raise resources for furthering the objectives of the University.

11.4.5.2 To grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice Chancellor and to make necessary arrangements for discharge of the functions of such officers during their absence.

11.4.5.3 To regulate and enforce discipline among the employees of the University and to take appropriate disciplinary action whenever necessary.

11.4.5.4 To entertain, adjudicate upon and if considered fit, to redress any grievances of the employees of the University, who may, for any reason fall aggrieved.

11.4.5.5 To select an emblem and to have a common seal for the University and to provide for the custody and use of such seal.

11.4.5.6 To conduct inspections and enquires in various departments, centres, institutions and affiliated colleges of the University and initiate corrective action wherever needed.

11.4.6 Formation of Committees :

The Board of Management may form such Committees for such purposes and with such powers as the Board may deem fit and co-opt such persons on these committees as it thinks fit.

12.0 Delegation of Powers :

The Governing Body and the Board of Management may by a resolution, delegate the the Vice Chancellor, the Registrar, the Standing Committee or the Ad-hoc Committee, such of its powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice Chancellor or the Standing Committee or the Ad-hoc Committee, or any of their Officers to whom such powers are delegated, shall be reported at the next meeting of the Governing Body and the Board of Management.

13.0 The Academic Council :

The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations, coordinate and exercise general control and supervision over the academic policies and programmes of the University and be responsible for the maintenance of standards of education, teaching and training, interdepartmental coordination, research, examination and tests within the University.

13.1 Constitution of the Academic Council :

13.1.1 The Academic Council shall consist of the following members :

(i) The Vice Chancellor - Chairman

(ii) The Registrar - Non Member Secretary

(iii) Deans/Associate Deans of various Schools/Colleges of the University and its Study Centres.

(iv) Three Faculty Members to the nominated by the Vice Chancellor.

(v) Three outside experts nominated by the Vice Chancellor.

13.1.2 The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

13.1.3 The term of the Members of the Academic Council other than the Ex-officio Members shall be two years. However, in the case of the employees of the University, the term shall end immediately after their relinquishing their office at the University.

13.1.4 Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and the Regulations, the Academic Council shall have the powers to control, regulate and maintain the standards of education, instruction and examination of the University and shall exercise such other powers and functions as may be conferred or imposed upon it by this Act, Statutes or the Ordinances.

13.1.5 The Vice Chancellor may invite such other persons as he may deem fit, to attend the meetings of the Academic Council from time to time. However, the inviteees shall not be eligible to vote on any of the resolutions of the Academic Council.

13.2 Disqualification of the Members of the Academic Council :

13.2.1 Where a person has become a Member of the Academic Council by reason of the office of appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

13.2.2 A member of the Academic Council shall cease to be a member in the folowing circumstances also:

(i) If the member resigns from the Academic Council.

(ii) If the member becomes mentally unsound.

(iii) If the members had been convicted of a criminal offence involving moral turpitude or any other reason, and a higher court has not stayed such conviction.

(iv) If the member fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council without-leave from the Chairman.

13.3 Meetings of the Academic Council :

13.3.1 The Academic Council shall meet as often as may be necessa

13.3.2 One third of the total members of the Academic Council shall constitute the quorum of the meeting of the Academic Council.

13.3.3 Resolutions of the Academic Council may be passed through circulation among all the members, except in cases where such Resolution are required to be passed at a meeting. The resolutions so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such Resolution had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the Resolution.

13.4 Functions and Powers of the Academic Council :

Subject to the provisions of the Act, Statutes and the Ordinances, the powers of the Academic Council shall include, interalia, the following:

13.4.1 To exercise general supervision over the academic work of the University and to give direction regarding methods of instructions, evaluation, research and improvement in the academic standards.

13.4.2 To report and act on any matter referred to or delegated to it by the Board.

13.4.3 To formulate different courses and programmes to be imparted to the students of the University.

13.4.4 To lay down the curriculum and frame syllabus for any of the courses and programmes offered by the University, and publish text books and other instructional material for the same.

13.4.5 To innovate, constantly upgrade and improve the syllabus to include emerging and futuristic technologies.

13.4.6 To make recommendations to the Board, with regard to creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments and the duties attached thereto.

13.4.7 To formulate and modify or revise schemes for the organisation of the faculties, colleges and schools and to assign to such faculties, schools and colleges, their respective subjects and also to report to the Board as to the expediency of the abolition or division or combination of one faculty, college and school with another.

13.4.8 To make regulations for lateral entry of students from other Universities/Boards of Technical Education of Indian or Foreign Origin.

13.4.9 To promote research activities and programmes, and to ask for, from time to time, reports on such research activities and programmes from faculties, colleges and schools.

13.4.10 To consider proposals submitted by the faculties, schools and colleges relating to instructions, teaching facilities, etc.

13.4.11 To appoint Committees for admission of students to the University.

13.4.12 To recognise Diplomas and Degrees of other Universities and institutions located in India and abroad and to determine their equivalence in relation to the Diplomas and Degrees of the University on reciprocal basis in consultation with the Association of Indian Universities (AIU).

13.4.13 To make regulations for awarding admission to Secondary, Post Secondary, Under-Graduate, Graduate, Post-Graduate and Doctoral programmes of the University to such candidates who do not posses formal University/Technical Education Board/Secondary Board of Education qualification otherwise mandatory for admission to such courses but have the prescribed age, quantifiable knowledge, skills and competencies in the related discipline.

13.4.14 To approve conferment of degrees, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honour on the basis of the results declared.

13.4.15 To make guidelines for the award of fellowships, stipends, scholarship, medals and prizes, etc., and empower the Vice Chancellor or any other officer of the University to approve the eligible candidates for such awards.

13.4.16 To prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations and to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts, as may be necessary, for the purposes of the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and/or the regulations.

13.4 17 To make recommendations to the Board of Management on :

(i) Measures for improving standards to teaching, training, research and examinations.

(ii) Institution of Fellowships, Exchange Programmes, Scholarships, Medals, Prizes, etc.

(iii) Regulation covering the academic functioning of the University and its departments, colleges and institutions, discipline, residence, admissions, examinations, award of fellowships and studentship, freeship, concessions, attendance, etc. and submit the same to the Board of Management for approval.

13.4.18 To suggest measures for departmental co-ordination.

13.4.19 To appoint Committees consisting of such members as the Academic Council may deem fit to deal with any of the matters ordinarily dealt with by the Academic Council.

13.4.20 To approve new courses not being offered by the University.

14.0 The Board of Advisors

The Governing Body may by a resolution constitute a Board of Advisors. The Board of Advisors w[illegible] render advice to the Governing Body as also the Board of Management in managing the affairs of the University and enhancing its academic standards. The members of the Board of Advisors shall consist of eminent educationists, industrialists and public figures besides selected members drawn from the Governing Body and the Academic Council and the schools, colleges and the study centres of the University in India and abraod.

15.0 Examination Committee

15.1 The Vice Chancellor shall constitute an Examination Committee for the purpose of recommending suitable persons for appointment as examiners for various examinations and for suggesting evaluation methods for each subject.

15.2 The Examination Committee shall consist of :

(i) The Vice Chancellor - Chairman

(ii) Controller of Examination - Member Secretary

(iii) Two Professors from the College/School of the University.

(iv) One Expert nominated by the Chancellor.

15.3 The Examination Committee shall recommend a panel of Examiners for each subject of the courses of study to the Vice Chancellor.

15.4 The Vice Chancellor shall ordinarily appoint Examiners from the panel recommended by the Examination Committee. He may appoint examiners outside the panel, if he deems it fit and necessary.

16.0 Results Committee

16.1 The Vice Chancellor shall constitute a Results Committee to approve the results of various examinations before they are declared.

16.2 The Results Committee shall consist of :

(i) Vice Chancellor - Chairman

(ii) Deans of Colleges/Schools of the University.

(iii) One Expert nominated by the Chancellor.

(iv) The Registrar.

(v) The Controller of Examination - Member Secretary.

17.0 The Finance Committee and its Constitution :

The Governing Body shall appoint the Finance Committee.

The Finance Committee shall consist of the following members :

(i) The Vice Chancellor

(ii) The Chief Finance and Accounts Officer.

(iii) Three Nominees of the Sponsoring Body.

The Vice Chancellor shall be the Chairman of the Committee and in his absence, one of the nominees of the Sponsoring Body shall preside over the meetings of the Committee.

17.1 Meetings of the Finance Committee

17.1.1 The Committee shall meet as often as necessary.

17.1.2 One third of the members of the Committee shall constitute the quorum.

17.1.3 The Chief Finance Officer shall call the meeting of the Finance Committee with the approval of the Vice Chancellor.

17.2 Powers and Functions of the Finance Committee :

17.2.1 To make recommendations on all financial matters to the Board.

17.2.2 To consider all proposals for capital expenditures and to make recommendations to the Board.

17.2.3 To examine the annual accounts of the University and advise the Board.

17.2.4 To examine the annual budget estimate and advise the Board thereon.

17.2.5 To review the financial position of the University periodically and recommend to the Board any action to be taken.

17.2.6 To keep a constant watch on the state of cash and bank balances and on the state of investments.

17.2.7 To ensure that the limit fixed by the Governing Body for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are spent for the purpose for which they have been granted/ allotted.

17.2.8 To review the internal controls and act on the comments of the internal auditors.

17.2.9 To make recommendations to the Board on all proposals involving the raising of funds, receipts and expenditure.

17.2.10 To determine and fix the fee payable by the students of the University and lay down the procedure thereof.

17.2.11 To fix the basis for charging consultancy and other fee to be charged by the University.

17.2.12 To generally perform and act on any of the activities that may be delegated by the Board or the Governing Body.

17.2.13 To recommend to the Board appropriate action against person(s) responsible for unauthorised expenditure and any financial irregularity.

17.2.14 To hold and manage the property and investments of the University including endowed property.

17.2.15 To ensure that the registers of the buildings, land, furniture and equipments are maintained up to date and that the stock taking is carried out periodically.

18.0 Selection Committee

18.1 The Board may appoint a Selection Committee to recommend names of the persons for the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and such other academic posts as may be prescribed by the Board of Management.

18.2 The Selection Committee so appointed shall consist of :

(i) Three experts in the relevant disciplines nominated by the Chancellor.

(ii) One Nominee of the Board of Management not connected with the University and not below the rank of a professor.

(iii) Dean of the Faculty.

(iv) The Vice Chancellor - Chairman.

19.0 Constitution of Standing Committee and Adhoc Committee

19.1 The Governing Body and/or the Board of Management may, by a resolution in a duty conducted meeting appoint a Standing Committee or an Adhoc Committee and/or Enquiry Committee by defining -

(i) The purpose of appointment.

(ii) The constitution

(iii) The tenure of the Committee

(iv) The financial budget

(v) The procedure to be adopted

(vi) The rights and obligations of the Committee

(vii) The facilities to be acquired and

(viii) Other matters relevant or incidental to complete the purpose for which it is appointed.

19.2 The Committee so appointed shall exercise their powers and functions within the delegated authority. Neither the University nor the Governing Body, nor the Board of Management shall be accountable for the authority of powers used outside the scope of delegation by such Committees.

19.3 Such Committees shall be automatically dissolved on the completion of their tenure or after completion of the tasks assigned to them by the authority appointing them unless extension in the tenure is granted by the said authority.

20.0 Advisory Committee

20.1 The Governing Body may appoint an Advisory Committee for the purpose of rendering advice to it and the Board in matters relating to the conduct of the affairs of the University or for such other purposes as it may prescribed from time to time.

The Advisory Committee shall consist of eminent people and also include the members of the Governing Body and the Representatives from Schools, Colleges and Study Centres of the University.

20.2 The Board may direct the Academic Council, Finance Committee and/or any other Committees set up under the Act or these Statutes to follow the recommendations of the Advisory Committee.

20.3 The Board shall define the functions and powers while establishing such Committees.

21.0 Service Conditions for Faculty Members, Officers and other Employees.

21.1 The Board shall formulate the terms and conditions of appointment and service of Faculty M embers, Officers and Employees.

21.2 The Registrar shall issue the appointment letters to Faculty Members, Officers and Employees in accordance with the policies and procedures as formulated by the Board.

22.0 General Fund

The University shall establish a fund which shall be called the General Fund to which shall be credited the following namely :

22.1 Fees and other charges received by the University.

22.2 Any contribution made by the Sponsoring Body.

22.3 Any income received from consultancy and other work undertaken by the University in pursuance of its objectives.

22.4 Trusts, bequests, donations, endowments and any other grants.

22.5 All other sums received by the University

22.6 The General Fund shall be used for the purposes enumerated in the Act.

23.0 Budget

23.1 The Chief Finance and Accounts Officer, with the approval of the Finance Committee, based on the proposed budgets received from different colleges, institutes of the University shall prepare an annual budget for the forthcoming financial year, and submit at least two months before the beginning of financial year to the Board for the purposes of approving the same. The Board, upon the merits may suggest modifications, alternations or additions or approve the same with or without modifications and such approved budget will be the annual budget of the University for the year.

23.2 No expenditure other than that provided in the budget shall be incurred by the colleges and institutes of University without the approval of the Finance Committee.

23.3 The Finance Committee may consider any revision of the Budget based on the recommendation of the Chief Finance and Accounts Officer and shall place the same for rectification by the Board, at a subsequent meeting of the Board.

24.0 Accounts and Audit

24.1 The accounting year of the University shall be from 1st April of a year to 31st March of the following year.

24.2 The accounts of various institutions, schools, colleges and campuses of the University shall be consolidated by the Chief Finance and Accounts Officer who shall prepare the final annual accounts, consisting of the Income and Expenditure Account and the Balance Sheet of the University and place the same before the Finance Committee for their comments. The appropriations or absorptions of excess of expenditure and income shall be decided by the Finance

Committee. The accounts will thereafter be adopted by the Board, after which they will be audited by the Auditors appointed by the Governing Body.

24.3 All the assets of the University shall be maintained in the name of the University and shall be used for the settlement of liabilities at the time of liquidation or closure of the University under Section 33 and 34 of the Act.

24.4 The accounts of the University shall be open to examination by the Chancellor, Vice Chancellor, Registrar, Auditor of the University and any other person authorised by the Governing Body or the Sponsoring Body for the purpose.

24.5 Every Balance Sheet and Income and Expenditure account of the University shall comply with the relevant accounting standard as may be prescribed by the Government of India in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards.

24.6 The Vice Chancellor shall place the audited financial statements before the Governing Body, alongwith the report of the Auditors for information.

24.7 The Chief Finance and Accounts Officer, thereafter along with the Annual Report of the University, shall submit such financial statements to the Visitor and the State Government as provided under Section 30 of the Act.

25.0 Arbitration in case of Disputes

25.1 The Vice Chancellor shall be responsible for resolution of disputes and grievances between the teachers, officers, other employees and the students of the University.

25.2 The Vice Chancellor may delegate the responsibility for arbitration to the Registrar or the Deans as he may deem fit.

25.3 Any person who is aggrieved of the decision of the Vice Chancellor may appeal to the Chancellor within 15 days of communication of the decision by the Vice Chancellor.

25.4. Where it is found necessary, the Chancellor may appoint an Arbitration Committee to arbitrate such disputes and grievances with such constitution and such powers as he may deem fit.

27.5 The procedures for arbitration of disputes shall be laid down by the Board.

26.0 Regulations and Manuals

26.1 Save as otherwise provided in the Act, and the Statutes, the Board may make Regulations, as empowered under Section 37 of the Act, to conduct the business of the University and

attain the objectives for which it is established. The Regulations may, interalia relate to the following :

26.1.1 Establishment of Schools/Colleges/Faculties and Halls of Residence.

26.1.2 The Courses of Study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University.

26.1.3 The grant of academic award and distinctions.

26.1.4 Number of seats in different programmes of the University, not otherwise prescribed for by any other statutory body authorised for the purpose.

26.1.5 Reservation of seats in different programmes of the University not otherwise prescribed for by any other statutory body authorised for the purpose.

26.1.6 Admission of the students and their enrolment

26.1.7 Fee and other charges payable by the students.

26.1.8 Examination and Student Assessment.

26.1.9 Award of scholarship, bursaries, fee waivers, etc. to students.

26.1.10 Discipline of students and staff.

26.1.11 Resolution of disputes among students and staff and procedure for arbitration.

26.1.12 Conferment of Honorary degrees to distinguished persons.

26.1.13 Finance and administration of the University.

26.2 The Board may appoint an Ad-hoc Committee to draft the Regulations and to prepare manuals for different departments/functions of the University.

26.3 The Committee appointed above, shall have such members as nominated by the Board and perform all the functions as required under the order of appointment/ constitution.

26.4 On satisfying themselves on the Regulations made out by the Committee appinted for the purpose, the Board may adopt them for the University.

26.5 Each and every authority and officer, teaching and non-teaching staff, members of the Committees and students are bound to adhere to the provisions and procedures laid down in the manual of instructions drafted for the purpose.

26.6 The Board shall have right to alter, amend, frame new rules and regulations which are not inconsistent with the provisions of the Act for the purpose of conducting the activities of the University for which it is established.

26.7 The establishment of Distance Education Study Centres, Academic Centres, Examination Centres, etc.

26.8 The creation, composition and functions of any Committee or Body, which is considered necessary for the work of the University.

26.9 The preparation and submission of budget estimates.

26.10 The procedure for convening a meeting of any authority and the conduct of the same.

27.0 Subsequent Statutes

The Governing Body may make, amend, alter, modify these First Statutes and the Ordinances as required for the administration of the University and submit the same to the Government for approval as per provision of the Act.

28.0 Ordinances

The Vice Chancellor of the University shall cause the Ordinances of the University to be made as per the provisions of Sections 27 of the Act and shall submit the same to the Government for its approval. He shall carry out the necessary changes in the Ordinances, as suggested by the Government, shall table the Ordinances after their due approval by the Government in the next meeting of the Governing Body. The Vice Chancellor shall follow similar procedure while making any moidifications to the Ordinances, or for introducing new Ordinances.

29.0 University to the be open to all Classes, Castes and Creed

29.1 The University shall be open to all persons irrespective of sex, caste, creed, religion, race, or class or place of domicile or nationality and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a Teacher of the University to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege there of;

29.2 Notwithstanding any thing contained in clause(a), the University shall make special provisions in the Regulations for the employment or profession of educational interests of women, persons with disability or of persons belonging to the weaker sections of the Society and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes as may be directed by the State Government from time to time.

30.0 Interpretation

30.1 In the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of the Statutes, Ordinances and Regulations, the provisions of the Act shall prevail.

30.2. The decision of the Government on interpretation shall be final and binding.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

क्रमांक 31/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	घुठिया प.ह.नं. 44	3.076	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.).	बिघुआ जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 38/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	झगरकापा प.ह.नं. 44	0.979	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.).	बिघुआ जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 39/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मदवानी प.ह.नं. 44	1.846	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.).	बिघुआ जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

क्रमांक 40/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	दरूवनकापा प.ह.नं.44	0.963	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ. ग.).	बिघुआ जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक भू-अर्जन/6-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-नगरदा, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.936 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2361	0.008
2360	0.068
2358/1	0.020
2348	0.080
2336/1	0.040
2336/2	0.056
2336/3	0.056
2347	0.076
2335	0.048
2280/2	0.008
2282	0.108
2278	0.052
2277	0.088
2267/5	0.040
2267/2	0.012
2267/6	0.048
2286	0.112
2287	0.056
510	0.004
2290	0.120
2291	0.008
2252	0.056
2251	0.012
2240	0.048
505	0.060
2241	0.024
2242	0.028
2243	0.008
2244	0.012
507/2	0.032
2245/1	0.032
2245/2	0.036
2148	0.028
2142/2	0.064
2138/1	0.028
2138/3	0.048
2138/4	0.036
504	0.012
509	0.016
507/1	0.032
2173/1	0.068
2173/2	0.088
511/2	0.060
योग 43	1.936

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 14 के माइनर चैन क्रमांक 45 एल. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक भू-अर्जन/9-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-नगरदा, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.376 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1991	0.160
2005/1	0.068
2005/2	0.020
1986/6	0.080
1987	0.112
1988	0.016
1980/3	0.044
1978	0.020
1976/1	0.032
1975/2	0.064
1977	0.048
2474	0.064
1971	0.040
2465/2	0.028
2465/1	0.052
2469	0.012
2477	0.040
2470	0.040
2476	0.020
2494/2	0.052
2495/2	0.024
2492	0.040
2491	0.012
2493/2	0.048
2494/1	0.004
2489	0.008
2482/1	0.028
2485/1	0.008
2485/2	0.028
2467	0.064
2490	0.048
2488/1	0.052
योग 32	1.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 14 के माइनर चैन क्रमांक 63 आर. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक भू-अर्जन/11-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमुड़ी, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.421 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.032
21	0.020
22	0.022
23/2	0.012
24	0.044
38	0.056
41	0.032
42	0.036

(1)	(2)
43	0.048
44/1	0.036
45	0.088
47/1	0.052
47/2	0.052
47/3	0.024
89/7	0.020
91/2	0.044
82	0.092
83	0.032
87/2	0.008
90/1	0.032
122/1	0.020
75/1	0.040
123/4	0.060
123/7	0.060
128	0.088
129/1	0.032
147	0.044
148/1	0.044
148/2	0.036
149/1	0.044
149/2	0.041
150	0.044
88/1	0.088
योग 33	1.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 12 के माइनर चैन क्रमांक 63 आर. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक भू-अर्जन/25-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मड़कड़ी, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.836 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1041	0.088
836	0.032
893	0.028
891/1, 892/2	0.036
1030	0.040
1039	0.008
1028	0.012
1026/5	0.040
1026/4	0.072
1025	0.048
888/2	0.060
1024/1	0.012
760/1, 2, 3	0.056
894/2	0.012
1024/2	0.052
1024/3	0.012
895/2	0.012
885/1	0.024
885/2	0.088
875/3	0.076
883/1	0.084
873/1	0.028
864	0.028
865	0.024
862	0.020
866	0.032
847/3	0.012
847/2	0.040
843	0.028
867/2	0.028
833/2	0.028

(1)	(2)
848	0.056
840/1	0.056
840/2	0.008
772	0.028
761/3	0.032
859	0.024
738	0.020
739	0.020
742	0.016
743	0.024
1029/1	0.020
892/1	0.028
894/3	0.014
892/2	0.032
894/1	0.014
895/1	0.016
1029/2	0.016
884/1	0.032
761/1	0.032
761/2	0.032
887/1	0.080
863/1	0.040
1	0.036
योग 55	1.836

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 12 के माइनर चैन क्रमांक 47 आर. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक भू-अर्जन/27-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाडुला, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.664 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
524	0.032
5213	0.040
521/2	0.060
521/1	0.032
521/4	0.008
159/16	0.080
168/17	0.120
159/15	0.080
159/14	0.088
159/12	0.052
522/1	0.064
522/2	0.008
योग 12	0.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 12 के माइनर चैन क्रमांक 25 एल. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक भू-अर्जन/28-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-सोनाडुला, प. ह. नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.276 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
535/1	0.012
535/4	0.068
534/8	0.020
534/7	0.056
534/3	0.020
530/7	0.032
530/2	0.068
योग 7	0.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 12 के माइनर चैन क्रमांक 11 एल. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2003

क्रमांक भू-अर्जन/29-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.828 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
295/6	0.104
188, 187/2	0.220
242/2	0.064
315/2	0.012
189/1	0.112
281	0.008
238/4	0.008
235/3	0.056
235/4	0.112
313/3	0.092
312/1	0.112
240/9	0.080
240/10	0.052
240/11	0.008
240/7, 240/8	0.136
312/2	0.072
313	0.072
325	0.180
300	0.032
299/2	0.040
299/3	0.028
295/2	0.092
295/3	0.020
301/2	0.040
301/1	0.080
योग 25	1.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 12 के माइनर चैन क्रमांक 80 आर. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/1-अ/82 वर्ष 98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-कसडोल
(ग) नगर/ग्राम-सेमरा, प. ह. नं. 154
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.01 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
125/1 ख	0.16
125/1 ग	0.41
125/1 ङ	0.28
125/1 च	0.41
651/2	0.15
652/3	0.20
650/1	0.02
650/2	0.23
529	0.15
589, 604, 640, 649	1.12
590	0.05
591	0.28
592	0.03
593	0.04
594	0.51
595	0.32
596	0.02
600	0.63
योग 18	5.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक नहर क्र. 4 के गिधौरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/2-अ/82 वर्ष 98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-कसडोल
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी, प. ह. नं. 156
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.59 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1623/2	1.02
1623/8	0.01
1623/16	0.40
1624/26	0.96
1624/2	0.20 (घास) शासकीय
योग 5	2.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के खपरीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि को नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/3-अ/82 वर्ष 98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-कसडोल

(ग) नगर/ग्राम-टुण्डरा, प. ह. नं. 155

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2223	0.43
3325/2, 3326/2, 3330/1	0.13
3378/1	0.15
3391/2	0.12
3329/1	0.04
3390	0.35
3367/2	0.17
3363	0.20
3330/2	0.08
2410/2	0.13
2256	0.05
योग 11	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक शाखा नहर क्र. 4 के खपरीडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक क/ भू-अर्जन/4-अ/82 वर्ष 98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-कसडोल

(ग) नगर/ग्राम-गिधौरी, प. ह. नं. 156

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
159/1	0.20
159/2 घ	0.15
160	0.39
163	0.47
164/3	0.32
164/1, 165, 166, 167	0.65
योग 6	2.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक नहर क्र. 4 के गिधौरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/5-अ/82 वर्ष 98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-मोहतरा, प. ह. नं. 155
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.11 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	34/1	0.61
	36/1	0.50
	177/1	1.00 (शासकीय घास)
योग	3	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक व्यपवर्तन योजना के वितरक नहर क्र. 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2003

क्रमांक भू-अर्जन/5-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बनाहिल, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.640 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	734/1	0.048
	734/2	0.036
	552/3	0.036
	552/1	0.040
	553/3	0.040
	553/5	0.032
	553/1	0.040
	556	0.152
	532	0.072
	531	0.104
	525	0.040
योग	11	0.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 14 के माइनर चैन क्रमांक 37 एल. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2003

क्रमांक भू-अर्जन/24-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कैथा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.256 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1	0.160

	(1)	(2)
	55	0.028
	44/1	0.068
योग	3	0.256

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 12 के माइनर चैन क्रमांक 25 एल. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2003

क्रमांक भू-अर्जन/26-अ/82 वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.376 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	380	0.064
	381/1	0.024
	381/2	0.016
	384/1	0.020
	384/2	0.020
	385	0.040
	388/2	0.144
	381/1, 2	0.048
योग	8	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोंक मुख्य नहर क्रमांक 12 के माइनर चैन क्रमांक 47 आर. के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव दिनांक 30 जुलाई 2003

क्रमांक 6550/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पटपर, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.19 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1090	1.60
1076/2	0.12

	(1)	(2)
	1076/4	0.11
	1076/1	0.10
	1096	2.00
	1097/1	0.90
	1075/1	0.22
	1097/2	0.85
	1089	0.12
	1088	0.22
	1080	1.00
	1082	0.10
	1081	0.30
	1077	0.90
	1076/3	0.25
	1071	0.85
	1070	0.15
	1028	0.25
	1029	0.08
	1069/3	0.07
योग	20	10.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरवाटोला जलाशय के अंतर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक 6714/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-मोहला

(ग) नगर/ग्राम-देवरसुर, प. ह. नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.90 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	9/12	0.47
	29	1.01
	32/4	0.60
	30	0.60
	133	0.32
	32/1	1.41
	32/2	1.20
	36	1.95
	39	5.35
	135/1	2.75
	37	1.28
	38/1	1.81
	40	0.25
	41	0.75
	42	0.34
	120/2	0.17
	121	1.15
	132	0.52
	134/2	0.90
	139	1.07
	135/2	1.50
	143	0.34
	130	0.16
योग	23	25.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरसुर जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव दिनांक 5 अगस्त 2003

क्रमांक 6715/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-मोहला

(ग) नगर/ग्राम-पाऊर खेड़ा, प. ह. नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-32.33 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
330/1	0.60
330/2	0.23
330/6	0.33
330/7	0.14
335	0.54
315	0.38
308	1.05
311	0.87
316	0.16
303/1	0.65
317	1.48
305	2.91
309	0.42
318	0.17
291/1	0.11
319/2	0.27
306	1.00
312	2.27
320	0.34
307	0.50
281/1	0.90
281/5	0.18
281/7	0.31
281/2	0.94
281/9	0.47
281/3	0.80
281/8	0.45
281/4	1.70
281/6	0.18
282/1	0.72
211/1	0.20
284/1	0.32
209	0.74
210/1	0.50
233/2	0.63
210/2	0.40
233/3	1.43
302/1	2.35
302/2	0.77
391/2	0.23
303/2	0.44
303/3	0.35
345/5	1.14
348/1	1.16
346	0.60
योग 45	32.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरसुर जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक 6733/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-मासुल, प. ह. नं. 2

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.30 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
6082/1	1.30
योग 1	1.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पटेवा-मासुल मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के न्यायालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव दिनांक 6 अगस्त 2003

क्रमांक 6734/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पटेवा, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.36 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1013	0.04
1017	0.04
1022	0.05
1018	0.04
1019	0.03
1020	0.02
1021	0.04
1023	0.02
1024	0.03
1025/1	0.60
1044	0.08
1048	0.10
1051	0.07
1838	0.02
1045	0.04
1047/1	0.04
1839/1	0.02
1047/2	0.04
1039/2	0.01
1449	0.04
1449/2	0.04
1052	0.18
1054	0.02
1056	0.12
1110	0.01
1111/2	0.01
1112/1	0.02
1115	0.01
1116	0.04
1775/1	0.03
1775/2	0.02
1775/8	0.02
1774	0.03
1823	0.05
1111/1	0.01
1860/1	0.07
1824/2	0.07
1824/3	0.04
1829	0.06
1830/1	0.07
1831	0.03
1843	0.09
1832/1	0.18
1844	0.08
1854	0.17
1855/1	0.02
1855/2	0.02
1855/3	0.06
1865	0.03
1871	0.06
1872	0.06

(1)	(2)
1873	0.06
1874	0.08
1875/1	0.05
1875/2	0.04
1866	0.04
योग	3.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पटेवा-मासुल मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के न्यायालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव दिनांक 18 अगस्त 2003

क्रमांक 7005/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बनबोड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
287	0.14
106/1	0.35
224	0.11
106/3	0.43
322/1	0.08
325/1	0.05
321/1	0.16
323	0.02
271	0.08
270/3	0.14
261/1	0.12
261/2	0.14
251	0.28
242	0.23
238	0.26
225/2	0.05
226/2	0.09
202/1	0.32
202/2	0.32
168	0.47
109	0.30
107/1	0.17
107/2	0.11
योग 23	4.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भंडारपुर जलाशय के अंतर्गत बनबोड़ मुख्य नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव दिनांक 18 अगस्त 2003

क्रमांक 7006/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-करेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.57 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
410	0.06
405	0.01
411	0.20
409	0.06
408	0.04
404	0.07
401	0.10
403	0.10
402	0.11
394	0.23
370	0.29
79	0.01
38/1	1.07
38/2	0.43
22	0.19
19	0.60
395	0.28
396	0.13
385/2	0.18
20	0.23
18	0.03
424	0.87
422	1.88
494	1.35
454	0.39
473	0.77
472/5	0.23
472/12	0.18
464/2	0.15
462	0.98
400/1	1.35
योग 31	12.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भंडारपुर जलाशय के अंतर्गत करेला मुख्य नहर, करेला माइनर एवं वेस्ट वीयर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.